



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 375]

नई दिल्ली, रविवार, जून 23, 2019/आषाढ़ 2, 1941

No. 375]

NEW DELHI, SUNDAY, JUNE 23, 2019/ASHADHA 2, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 2019

सं. 25/2019- सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 444(अ).—जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित “डक्टाइल आयरन पाइप्स” (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51), (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 7303 00 30 या 7303 00 90 के अंतर्गत आते हैं, के मामले में अधिसूचना संख्या 15/1006/2012-डीजीएडी, दिनांक 04 सितम्बर, 2013, जिसे दिनांक 04 सितम्बर, 2013 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों में इस विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत माल पर प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की थी;

और जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर, केन्द्र सरकार ने, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 23/2013-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 10 अक्टूबर, 2013, जिसे सा.का.नि. 680 (अ), दिनांक 10 अक्टूबर, 2013, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत विषयगत माल पर दिनांक 10 अक्टूबर, 2013 से प्रतिपाटन शुल्क लगाया था;

और जहां कि मैसर्स जिंदल साँ लिमिटेड के द्वारा दायर स्पेशल सिविल एप्लीकेशन संख्या 12368/2018 के मामले में आए माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांक 26 सितम्बर, 2018 के निर्णय के अनुपालन में केन्द्र सरकार ने भारत

सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 51/2018-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 09 अक्टूबर, 2018, जिसे सा.का.नि. 1012 (अ), दिनांक 09 अक्टूबर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा उक्त विषयगत वस्तु पर प्रतिपाटन शुल्क को 09 अप्रैल, 2019 तक बढ़ा दिया था;

और जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात के बारे में अधिसूचना संख्या 7/18/2018-डीजीएडी, दिनांक 09 अक्टूबर, 2018 जिसे दिनांक 09 अक्टूबर, 2018 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत सनसैट रिव्यू जांच शुरू की थी;

और जहां कि उक्त सनसैट रिव्यू जांच के पूरा हो जाने पर निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात के बारे में अधिसूचना संख्या 7/18/2018-डीजीएडी, दिनांक 01 अप्रैल, 2019, जिसे दिनांक 01 अप्रैल, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों को जारी किया है और निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने उक्त निष्कर्षों के आधार पर इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने की जरूरत नहीं है और उन्होंने चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क को और आगे जारी रखने की सिफारिश नहीं की थी;

और जहाँ मैसर्स जिंदल सॉ लिमिटेड के द्वारा माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किए गए स्पेशल सिविल एप्लीकेशन संख्या 6896/2019 के मामले में दिनांक 05 अप्रैल, 2019 को आए माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में केन्द्र सरकार ने विषयगत वस्तु पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 18/2019-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 10 अप्रैल, 2019, जिसे सा.का.नि. 299(अ) दिनांक 10 अप्रैल, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था के द्वारा 09 मई, 2019 तक के लिए बढ़ा दिया था;

और जहाँ कि मैसर्स जिंदल सॉ लिमिटेड द्वारा माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किए गए स्पेशल सिविल एप्लीकेशन संख्या 6896/2019 के मामले में आए माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांक 03 मई, 2019 के निर्णय के अनुपालन में केन्द्र सरकार ने विषयगत वस्तु पर लगने वाले शुल्क को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 21/2019-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 09 मई, 2019, जिसे सा.का.नि. 352 (अ.), दिनांक 09 मई, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा 23 जून, 2019 तक बढ़ा दिया है;

और जहां कि मैसर्स जिंदल सॉ लिमिटेड के द्वारा दायर स्पेशल सिविल एप्लीकेशन नं. 6896/2019 के मामले में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने अपने 20 जून, 2019 के आदेश में आगे यह भी आदेश दिया है कि-

“इस स्तर पर इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि धारा 9क (5)” के प्रावधानों के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क की बढ़ाई जा सकने वाली अवधि 09 अक्टूबर, 2019 तक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादी संख्या 2 को अपने अंतिम निष्कर्ष देने की प्रक्रिया अधिकतम 15 सितम्बर, 2019 तक पूरी करनी होगी और प्रतिवादी संख्या 1 को धारा 9क के प्रावधानों और नियमावली के अनुसार उपयुक्त अवधि तक प्रतिपाटन शुल्क को बढ़ाना होगा जिससे कि यह संपूर्ण प्रक्रिया/कार्यवाही व्यर्थ न होने पाए।

अतः अब, सीमा शुल्क टैरिफ (पाठित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पठित, उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 20 जून, 2019 को आए माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में केन्द्र सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 23/2013, सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 10 अक्टूबर, 2013, जिसे सा.का.नि. 680 (अ), दिनांक 10 अक्टूबर, 2013 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 3 में, अंक, अक्षर और शब्द "23 जून, 2019" के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द "09 अक्टूबर, 2019" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 354/3/2007-टीआरयू (पार्ट. I)]

रूचि बिष्ट, अवर सचिव

नोट - प्रधान अधिसूचना संख्या 23/2013, सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 10 अक्टूबर, 2013 को सा.का.नि. 680 (अ), दिनांक 10 अक्टूबर, 2013 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 21/2019- सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 09 मई, 2019, जिसे सा.का.नि. 352 (अ.), दिनांक 09 मई, 2019 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd June, 2019

No. 25/2019-Customs (ADD)

G.S.R.444 (E).—Whereas in the matter of 'Ductile iron pipes' (hereinafter referred to as the subject goods) falling under tariff items 7303 00 30 or 7303 00 90 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country), and imported into India, the designated authority in its final findings *vide* notification number 15/1006/2012-DGAD, dated the 4th September, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 4th September, 2013, had recommended continuation of anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating in, or exported from the subject country;

And whereas, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed anti-dumping duty on the subject goods with effect from the 10th October, 2013 *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 23/2013-Customs (ADD), dated the 10th October, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 680 (E), dated the 10th October, 2013;

And whereas, in pursuance of the Judgement dated the 26th September, 2018 of Hon'ble High Court of Gujarat in the matter of Special Civil Application No. 12368 of 2018, filed by M/s Jindal Saw Limited, the Central Government had extended the anti-dumping duty on the subject goods upto the 9th April, 2019 *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 51/2018-Customs (ADD) dated the 9th October, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1012 (E), dated the 9th October, 2018;

And whereas, the designated authority had initiated the review investigation *vide* notification No. 7/18/2018-DGAD, dated the 9th October, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 9th October, 2018, concerning imports of subject goods originating in or exported from China PR;

And whereas, on completion of review investigation, the designated authority issued final finding *vide* notification No. 7/18/2018-DGAD, dated the 1st April, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 1st April, 2019 concerning imports of subject goods originating in or exported from China PR and the designated authority *vide* the said findings concluded that continuation of anti-dumping duty is not warranted and did not recommend further extension of anti-dumping duty on import of subject goods originating in or exported from China PR;

And whereas, in pursuance of the Judgement dated the 5th April, 2019 of Hon'ble High Court of Gujarat in the matter of Special Civil Application No. 6896 of 2019, filed by M/s Jindal Saw Limited, the Central Government had extended the anti-dumping duty on the subject goods upto the 9th May, 2019 *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 18/2019-Customs (ADD), dated the 10th April, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 299 (E), dated the 10th April, 2019;

And whereas, in pursuance of the Judgement dated the 3rd May, 2019 of Hon'ble High Court of Gujarat in the matter of Special Civil Application No. 6896 of 2019, filed by M/s Jindal Saw Limited, the Central Government had extended the anti-dumping duty on the subject goods upto the 23rd June, 2019 *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 21/2019-Customs (ADD), dated the 9th May, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 352 (E), dated the 9th May, 2019;

And whereas, the Hon'ble High Court of Gujarat in the matter of Special Civil Application No. 6896 of 2019, filed by M/s Jindal Saw Limited, *vide* order dated the 20th June 2019, has ordered:

“At this stage, it is required to be noted that as per the provisions of the Section 9A(5), the extendable period of anti-dumping duty is 09.10.2019. In that view of the matter, the respondent no. 2 shall complete the process of rendering final findings latest by 15.09.2019 and the respondent no. 1 shall extend the anti-dumping duty by suitable period in accordance with the provisions of Section 9A and the Rules so as to prevent the entire exercise becoming infructuous.”

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 and in pursuance of the order of the Hon'ble High Court of Gujarat dated the 20th June, 2019, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 23/2013, Customs (ADD), dated the 10th October, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 680 (E), dated the 10th October, 2013, namely:-

In the said notification, in paragraph 3, for the figures, letters and words “23rd June 2019”, the figures, letters and words “9th October 2019” shall be substituted.

[F. No. 354/3/2007-TRU (Pt. I)]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Note:- The principal notification No. 23/2013- Customs (ADD), dated the 10th October, 2013 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 680 (E), dated the 10th October, 2013 and last amended *vide* notification No.21/2019-Customs (ADD) dated the 9th May, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 352(E), dated the 9th May, 2019.